भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं.4248**
वाणिज्य विभाग

दिनांक 19 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

आयात शुल्क में कमी

4248. श्री पुट्टा महेश कुमार:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कच्चे खाद्य तेलों के आयात शुल्क में कमी के कारण भारतीय पाम ऑयल किसानों पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन/सर्वेक्षण किया है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारत में, विशेषकर आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले में, भारतीय पाम ऑयल किसानों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) क्या सरकार ने कच्चे पाम ऑयल की कीमतों को स्थिर बनाए रखने के लिए एक गतिशील आयात शुल्क तंत्र का उपयोग करने पर विचार किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) क्या सरकार ने कच्चे पाम ऑयल पर आयात शुल्क में कमी के कारण राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम (एनएमईओ-ओपी) के कार्यान्वयन पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव पर विचार किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ऑयल पाम (एनएमईओ-ओपी) का क्रियान्वयन कर रहा है, जिसके अंतर्गत एलुरु जिले सहित आंध्र प्रदेश में ऑयल पाम किसानों को एक व्यापक सहायता पैकेज प्रदान किया जाता है, जिसमें रोपण सामग्री, अंतर-फसल, सिंचाई, मशीनीकरण, पुनः रोपण, क्षमता निर्माण, उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने और नर्सरी, बीज उद्यान और प्रसंस्करण मिलों जैसे बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्तीय सहायता शामिल है।

इसके अलावा, एलुरु ज़िले सहित आंध्र प्रदेश के संबंध में, राज्य सरकार प्रत्येक माह तेल निष्कर्षण अनुपात (ओईआर) और कर्नेल नट मूल्य जैसे कारकों पर विचार करते हुए, सीएसीपी-अनुशंसित फॉर्मूले के आधार पर ताज़ा फलों के गुच्छे (एफएफबी) की कीमत घोषित करती है। अधिसूचित फ़ैक्टरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उद्योगों को किसानों से इसी मूल्य पर एफएफबी खरीदना अनिवार्य है।

(ग) और (घ): भारत में खाद्य तेलों पर गतिशील आयात शुल्क संरचना के कुछ नुकसान हैं क्योंकि भारत अपनी लगभग 60% खाद्य तेल आवश्यकताओं के लिए आयात पर निर्भर करता है और घरेलू कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार दरों से अत्यधिक प्रभावित होती हैं। वैश्विक कीमतों में अत्यधिक अस्थिरता के कारण, गतिशील आयात शुल्क प्रणाली का उपयोग करने से घरेलू बाजार में कीमतों को प्रभावी ढंग से स्थिर या नियंत्रित करना संभव नहीं है।

कच्चे सूरजमुखी, सोयाबीन और पाम तेल सहित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) को 20% से घटाकर 10% करने का उद्देश्य खाद्य तेलों की कीमतों पर मुद्रास्फीति के दबाव को कम करना है, जो सितंबर 2024 में पहले की गई शुल्क वृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में हुई वृद्धि के कारण बढ़ गया था। कच्चे तेलों पर आयात शुल्क में कमी से कच्चे और परिष्कृत खाद्य तेलों के बीच 19.25% का शुल्क अंतर पैदा हो गया है। इस उच्च शुल्क अंतर के लाभों में शामिल हैं:

(i) आरबीडी पामोलीन के आयात को हतोत्साहित करना, जिसे कच्चे पाम तेल (सीपीओ) से परिष्कृत किया जाता है, जिससे कच्चे तेलों के घरेलू शोधन को बढ़ावा मिलेगा।

(ii) घरेलू शोधन के लिए सीपीओ का आयात, जिसके परिणामस्वरूप पाम स्टीयरिन और पाम फैटी एसिड डिस्टिलेट्स (पीएफएडी) जैसे उप-उत्पादों की उपलब्धता बढ़ गई।

(iii) उप-उत्पाद अधिक किफायती होंगे, जिससे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएम्सीजी) उद्योग को लाभ होगा। इससे घरेलू और व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों जैसी विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में संभावित कमी आ सकती है।

(iv) घरेलू रिफाइनरियों की उच्च क्षमता उपयोग से उच्च मूल्य संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा तथा स्थानीय खाद्य तेल रिफाइनिंग उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।

*****